

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1173
TO BE ANSWERED ON 25.11.2019

Vocational Training in Schools

1173. SHRIMATI KIRRON KHER:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) the number of schools which offer vocational training in the country, State/ UT-wise including Chandigarh;
- (b) the details of the various subjects in which vocational training is being provided to the students in Government schools; and
- (c) whether the schools have been equipped with the necessary infrastructure and teachers to impart digital education to the students and if so, the details thereof?

ANSWER
MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(a) The Government is implementing the scheme of Vocationalisation of School Education under the umbrella of 'Samagra Shiksha - an integrated scheme for school education', a Centrally Sponsored Scheme. Till 2018-19, the scheme of Vocationalisation of School Education has been implemented in 8654 schools. State/UT-wise statement indicating number of schools where the scheme has been implemented is enclosed at Annexure.

(b) The scheme of Vocationalisation of School Education covers 55 job roles in 19 sectors i.e. Agriculture, Apparel Made ups & Home Furnishing, Automotive, Banking Finance and Insurance Services, Beauty and Wellness, Construction, Electronics & Hardware, Healthcare, Information Technology / Information Technology Enabled Services (IT/ITeS), Media & Entertainment, Multi Skilling, Physical Education & Sports, Plumber, Power, Retail, Security, Telecom, Tourism & Hospitality, Transportation Logistics & Warehousing.

(c) In order to equip the schools with the necessary infrastructure to impart digital education to the students, there is a provision for setting up of Information and Communication Technology (ICT) laboratories in Government schools for classes VI to XII under Samagra Shiksha. The scheme provides supports to the States & UTs to provide Tablets/Laptops/Notebooks/integrated teaching learning devices and open source operating systems. It also includes support for digital boards, smart classrooms, virtual classrooms on pro-rata basis for number of schools approved and for development & provision of digital content. 106454 schools have so far been approved under the ICT component till 2019-20.

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 1173 TO BE ANSWERED ON 25.11.2019 ASKED BY SHRIMATI KIRRON KHER REGARDING VOCATIONAL TRAINING IN SCHOOLS.

IMPLEMENTATION STATUS OF THE VOCATIONALISATION OF SCHOOL EDUCATION

S. No.	State	No. of Schools Implemented
1	A & N	31
2	Andhra Pradesh	256
3	Arunachal Pradesh	99
4	Assam	251
5	Bihar	0
6	Chandigarh	16
7	Chhattisgarh	546
8	D N H	0
9	Daman & Diu	0
10	Delhi	22
11	Goa	97
12	Gujarat	20
13	Haryana	1051
14	Himachal Pradesh	873
15	Jammu & Kashmir	352
16	Jharkhand	260
17	Karnataka	150
18	Kerala	0
19	Lakshadweep	0
20	Madhya Pradesh	626
21	Maharashtra	508
22	Manipur	42
23	Meghalaya	23
24	Mizoram	27
25	Nagaland	18
26	Odisha	434
27	Puducherry	0
28	Punjab	780
29	Rajasthan	905
30	Sikkim	184
31	Tamil Nadu	67
32	Telangana	192
33	Tripura	24
34	Uttar Pradesh	200
35	Uttarakhand	0
36	West Bengal	600
Total		8654

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1173
उत्तर देने की तारीख: 25.11.2019
विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

1173. श्रीमती किरण खेर:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले विद्यालयों की चंडीगढ़ सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ख) विभिन्न विषयों का ब्यौरा क्या है जिसमें सरकारी विद्यालयों में छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है; और
- (ग) क्या विद्यालय छात्रों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और शिक्षकों से युक्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): सरकार, 'समग्र शिक्षा-स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना' की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा में व्यवसायी शिक्षा की योजना कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2018-19 तक स्कूल शिक्षा में व्यवसायी शिक्षा की योजना को 8654 स्कूलों में कार्यान्वित किया गया है। उन स्कूलों को निर्दिष्ट करने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है, जहां यह योजना कार्यान्वित की गई है।

(ख): स्कूल शिक्षा में व्यवसायीकरण की योजना में कृषि, निर्मित वस्त्र और गृह साज-सज्जा, ऑटोमोटिव, बैंकिंग वित्त और बीमा सेवाएं, सौंदर्य और स्वस्थता, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकि/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटी/आईटीईएस), मीडिया और मनोरंजन, मल्टी स्कीलिंग, शारीरिक शिक्षा और खेल, प्लम्बर, पावर, रीटेल, सुरक्षा, टेलीकॉम, पर्यटन और सत्कार, परिवहन लॉजिस्टिक्स और भंडारण जैसे 19 क्षेत्रों में 55 व्यवसायों से संबंधित अध्ययन शामिल हैं।

(ग): छात्रों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने में आवश्यक अवसरचना से स्कूलों को लैस करने के लिए सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा VI से XII के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का प्रावधान है। इस योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक्स/एकीकृत शिक्षण अधिगम उपकरण और ओपन सोर्सऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रदान करने हेतु उनकी सहायता की जाती है। इसमें अनुमोदित स्कूलों की संख्या के लिए यथानुपात आधार पर डिजिटल बोर्डों, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम और डिजिटल सामग्री के विकास और प्रावधान के लिए सहायता शामिल है। 2019-20 तक आईसीटी संघटक के तहत अब तक 106454 स्कूलों को अनुमोदित किया गया है।

विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में श्रीमती किरण खेर द्वारा दिनांक 25.11.2019 को लोक सभा में पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 1173 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्कूल शिक्षा के व्यावसायीकरण की कार्यान्वयन स्थिति

क्र. सं.	राज्य	क्रियान्वित स्कूलों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31
2	आंध्र प्रदेश	256
3	अरुणाचल प्रदेश	99
4	असम	251
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	16
7	छत्तीसगढ़	546
8	दादरा और नागर हवेली	0
9	दमन और दीव	0
10	दिल्ली	22
11	गोवा	97
12	गुजरात	20
13	हरियाणा	1051
14	हिमाचल प्रदेश	873
15	जम्मू और कश्मीर	352
16	झारखंड	260
17	कर्नाटक	150
18	केरल	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	626
21	महाराष्ट्र	508
22	मणिपुर	42
23	मेघालय	23
24	मिजोरम	27
25	नगालैंड	18
26	ओडिशा	434
27	पुडुचेरी	0
28	पंजाब	780
29	राजस्थान	905
30	सिक्किम	184
31	तमिलनाडु	67
32	तेलंगाना	192
33	त्रिपुरा	24
34	उत्तर प्रदेश	200
35	उत्तराखंड	0
36	पश्चिम बंगाल	600
कुल		8654
